

संपादकीय

कोलकाता में एक प्रशिक्षण चिकित्सक की बलाकार के बाद हत्या की घटना ने सभी संवेदनशील लोगों के भूतुरुद्धू और आकोश भर दिया है। यह बेवजह नहीं है कि बड़ी तादाद में लोगों ने इस मामले में न्याय सुनिश्चित करने से लेकर महिलाओं के खिलाफ अपराध पर काबू पाने के लिए एक कारोबार व्यवस्था बनाने के लिए आवाज उठाई है। इसी के तहत कई राज्यों में सरकारी अस्पतालों के चिकित्सकों ने हड्डताल कर कर दी, जिससे वहाँ काम करने और सरकारी विविध वर्गों की विषय बताते हुए हड्डताल वापस लेने और काम पर लौटने की अपील की ओर कहा कि चिकित्सकों के काम से दूर रहने से समाज के उन वर्गों पर असर पड़ता है, जिन्हें चिकित्साये देखभाल की ज़रूरत है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि न्याय और चिकित्सा को रोकने नहीं जा सकता। हड्डताल की वजह से खासीर पर गरीब तबकों से आने वाले मरीजों को हो रही दिक्कतों का अंदाजा भर लगाया जा सकता है।

विडंबना यह है कि हड्डताल से उन मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जो मजबूती में इलाज करने वाले पहुंचते हैं। कोलकाता की घटना पर दुख के समान पिछले

कुछ दिनों से यह सबाल भी चिंता की वजह बन रहा था कि चिकित्सकों की हड्डताल की वजह से जो समस्या खड़ी हो रही है, उनका समाधान क्या मसले पर सुनवाई के द्वारा चिकित्सकों की सुरक्षा और सरकारी विविध वर्गों का विषय बताते हुए हड्डताल वापस लेने और काम पर लौटने की अपील की ओर कहा कि चिकित्सकों के काम से दूर रहने से समाज के उन वर्गों पर असर पड़ता है, जिन्हें चिकित्साये देखभाल की ज़रूरत है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि न्याय और चिकित्सा को रोकने नहीं जा सकता। हड्डताल की वजह से खासीर पर गरीब तबकों से आने वाले मरीजों को हो रही दिक्कतों का अंदाजा भर लगाया जा सकता है।

ऐसे तामाल लोग होते हैं, जो किसी बीमारी के



चिकित्सक से इलाज या आपरेशन करने का समय लेते हैं और बहुत मुश्किल से उन्हें किसी

वजह से उन्हें यह कहा जाए कि आपका इलाज नहीं हो सकता, तो इसे कैसे देखा जाएगा। दूसरी ओर, सरकारी अस्पतालों में हड्डताल की वजह से अगर कोई मरीज मजबूती में निजी अस्पतालों या कल्याणी कोंडों में इलाज के लिए पहुंचता है तो वहाँ उसे आर्थिक खर्च की किस कसाठी को पूरा करना पड़ता है, यह छिपा नहीं है।

निश्चित रूप से एक बेंटद तकलीफदेह घटना पर चिकित्सकों का आंदोलित होना और प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है। इस आंदोलन को समाज के सभी संवेदनशील लोगों का समर्थन मिला है। मारा इसको वजह से सरकारी अस्पतालों के कामकाज में जिस स्तर की मुश्किल पेश आई है, वह भी चिंताजनक है। यों सुनील कोट्टी की अपील के बाद दिल्ली में ऐसे और रामगढ़ाहर लोहिया अस्पताल के

चिकित्सकों ने अपनी हड्डताल खत्म करने और इसी पर जाने की घोषणा कर दी, मारा कुछ राज्यों में अभी भी अस्पतालों की सेवाएं प्रभावित हैं।

गैरप्रतिवाद है कि चिकित्सकों की शिकायतों को सुनने के लिए एक समिति का गठन करिया गया है। वहीं सुनील आंदोलन ने अपनी स्थिति रपट में जिस तरह की लापरवाहियों और सबूतों से डेढ़छाड़ की ओर संकेत किया है, वह बागल पुलिस और राज्य सरकार के रुखों को कठोर में खड़ा करता है। ऐसी स्थिति में इस मसले पर चिकित्सकों सहित सभी लोगों की जिंदा समझी जा सकती है। मगर यह ध्यान रखने की जरूरत है कि किसी आंदोलन से व्यापक स्तर पर बैसे लोगों के जीवन के सामने संकर न चैद हो, जो फहले ही बीमारी से घिर कर रहे हैं।

मग्र सरकार के दो निर्णयों की यूनिसेफ ने भी की सराहना

‘

महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार में दोहरा रवैया

यूनिसेफ पूर्व से ही (यूनिसेफ) की भारतीय इकाई भारत

सरकार के साथ मिलकर स्कूल हाईजीन और मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य जागरूकता की दिशा में अग्रियान चलाये हुए है। विगत सप्ताह मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने छात्राओं के सम्मान व उनसे संवाद के एक कार्यक्रम में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रदेश की उम्मीद लाख छात्राओं के आरोप है। ये मामले जानावाहिर रहे हैं, मगर इसे एक बार पिछे एसेमिशन फार डेमोक्रेटिक रिसर्च ने जारी किया है, जिसमें फिल्मों पांच वर्ष में महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामलों का सामना कर रहे एक योग्य राजनीतिशील विधायियों द्वारा किया गया है। इसमें सोलह पर बलाकार जैसे जघ्य अपराध का आरोप है। सभी आरोपों के सिफर राजनीतिशील विधायियों द्वारा या सामित्र बताकर राखा जा सकता है। यह दिग्बोरा यहाँ रहे हैं और उनमें से कई जांत कर रही हैं। यह बेवजह नहीं है कि जनप्रतिवादी भी बन जाते हैं, जिन पर गंभीर अपराधों के आरोप होते हैं। अगर किसी जनप्रतिवादी पर महिलाओं के खिलाफ जघ्य अपराध करने या उसमें शामिल होने का आरोप होता है, तो

उससे महिलाओं के हक में इमानदार लड़ाई की कितनी उम्मीद की जा सकती है! जनता के नुमाइंदे कहे जाने वाले जो लोग खुद गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप होते हैं, वह कानून बनाने या बचाने के दायित्व के प्रति कहे गंभीर रूप से सकते हैं? यह बेवजह नहीं है कि जुनावी नैतिकता और शारीरिकी की मांग के बावजूद आज भी अच्छी-खासी संख्या में ऐसे जनप्रतिवादी हैं, जिन पर गंभीर अपराधों के आरोप हैं। ये मामले जानावाहिर रहे हैं, मगर इसे एक बार पिछे एसेमिशन फार डेमोक्रेटिक रिसर्च ने जारी किया है, जिसमें फिल्मों पांच वर्ष में महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामलों का सामना कर रहे एक योग्य राजनीतिशील विधायियों द्वारा किया गया है। इसमें सोलह पर बलाकार जैसे जघ्य अपराध का आरोप है। सभी आरोपों के सिफर राजनीतिशील विधायियों द्वारा या सामित्र बताकर राखा जा सकता है। यह दिग्बोरा यहाँ रहे हैं और उनमें से कई जांत कर रही हैं। यह बेवजह नहीं है कि जनप्रतिवादी भी बन जाते हैं, जिन पर गंभीर अपराधों के आरोप होते हैं। अगर किसी जनप्रतिवादी पर महिलाओं के खिलाफ जघ्य अपराध करने या उसमें शामिल होने का आरोप होता है, तो

उससे महिलाओं के हक में इमानदार लड़ाई की कितनी उम्मीद की जा सकती है! जनता के नुमाइंदे कहे जाने वाले जो लोग खुद गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप होते हैं, वह कानून बनाने या बचाने के दायित्व के प्रति कहे गंभीर रूप से सकते हैं? यह बेवजह नहीं है कि जुनावी नैतिकता और शारीरिकी की मांग के बावजूद आज भी अच्छी-खासी संख्या में ऐसे जनप्रतिवादी हैं, जिन पर गंभीर अपराधों के आरोप हैं। ये मामले जानावाहिर रहे हैं, मगर इसे एक बार पिछे एसेमिशन फार डेमोक्रेटिक रिसर्च ने जारी किया है, जिसमें फिल्मों पांच वर्ष में महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामलों का सामना कर रहे एक योग्य राजनीतिशील विधायियों द्वारा किया गया है। इसमें सोलह पर बलाकार जैसे जघ्य अपराध का आरोप है। सभी आरोपों के सिफर राजनीतिशील विधायियों द्वारा या सामित्र बताकर राखा जा सकता है। यह दिग्बोरा यहाँ रहे हैं और उनमें से कई जांत कर रही हैं। यह बेवजह नहीं है कि जनप्रतिवादी भी बन जाते हैं, जिन पर गंभीर अपराधों के आरोप होते हैं। अगर किसी जनप्रतिवादी पर महिलाओं के खिलाफ जघ्य अपराध करने या उसमें शामिल होने का आरोप होता है, तो

उससे महिलाओं के हक में इमानदार लड़ाई की कितनी उम्मीद की जा सकती है! जनता के नुमाइंदे कहे जाने वाले जो लोग खुद गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप होते हैं, वह कानून बनाने या बचाने के दायित्व के प्रति कहे गंभीर रूप से सकते हैं? यह बेवजह नहीं है कि जुनावी नैतिकता और शारीरिकी की मांग के बावजूद आज भी अच्छी-खासी संख्या में ऐसे जनप्रतिवादी हैं, जिन पर गंभीर अपराधों के आरोप हैं। ये मामले जानावाहिर रहे हैं, मगर इसे एक बार पिछे एसेमिशन फार डेमोक्रेटिक रिसर्च ने जारी किया है, जिसमें फिल्मों पांच वर्ष में महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामलों का सामना कर रहे एक योग्य राजनीतिशील विधायियों द्वारा किया गया है। इसमें सोलह पर बलाकार जैसे जघ्य अपराध का आरोप है। सभी आरोपों के सिफर राजनीतिशील विधायियों द्वारा या सामित्र बताकर राखा जा सकता है। यह दिग्बोरा यहाँ रहे हैं और उनमें से कई जांत कर रही हैं। यह बेवजह नहीं है कि जनप्रतिवादी भी बन जाते हैं, जिन पर गंभीर अपराधों के आरोप होते हैं। अगर किसी जनप्रतिवादी पर महिलाओं के खिलाफ जघ्य अपराध करने या उसमें शामिल होने का आरोप होता है, तो

उससे महिलाओं के हक में इमानदार लड़ाई की कितनी उम्मीद की जा सकती है! जनता के नुमाइंदे कहे जाने वाले जो लोग खुद गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप होते हैं, वह कानून बनाने या बचाने के दायित्व के प्रति कहे गंभीर रूप से सकते हैं? यह बेवजह नहीं है कि जुनावी नैतिकता और शारीरिकी की मांग के बावजूद आज भी अच्छी-खासी संख्या में ऐसे जनप्रतिवादी हैं, जिन पर गंभीर अपराधों के आरोप हैं। ये मामले जानावाहिर रहे हैं, मगर इसे एक बार पिछे एसेमिशन फार डेमोक्रेटिक रिसर्च ने जारी किया है, जिसमें फिल्मों पांच वर्ष में महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामलों का सामना कर रहे एक योग्य राजनीतिशील विधायियों द्वारा क

संक्षिप्त समाचार

10 टुकड़ों में बंट जाएगा वंडर इलेक्ट्रिकल्स का शेयर, कंपनी ने किया ऐलान



नई दिल्ली, एजेंसी। वंडर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने स्टॉक स्प्लिट का ऐलान किया है। कंपनी ने एक शेयर को 10 हिस्सों में बंटा जाएगा। हालांकि, इस फैसले पर निवेशक बहुत खुश नहीं दिखे। बता दें, पिछले एक साल के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। 22 अगस्त को शेयर बाजारों को दी जानकारी में कहा गया है कि 10 रुपये के फैस वैल्यू वाले एक शेयर को 10 हिस्सों में बंटा जाएगा। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयरों की फैस वैल्यू घटकर 1 रुपये हो जाएगी। कंपनी ने इस स्टॉक स्प्लिट के लिए अभी तक रिकॉर्ड डेटा का ऐलान नहीं किया है। लेकिन उम्मीद है कि अब वाले समय में कंपनी रिकॉर्ड डेटा का ऐलान कर सकती है। शुक्रवार को कंपनी के शेयर गुरुवार की क्रॉसिंग की तुलना में बढ़त के साथ 1617.85 रुपये के लेवल पर खुला था। वहीं, कंपनी के शेयर 1620 रुपये के इंटर्न-डे हाई पर पहुंच गए थे। यह कंपनी का 52 वीक हाई है। हालांकि, इस स्तर पर पहुंचने के लेवल पर बंट हुआ है। बीते एक साल के दौरान वंडर इलेक्ट्रिकल्स के शेयरों की कीमतों में 529 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 6 महीने से स्टॉक का होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 294 प्रतिशत का लाभ मिला है। बीते एक महीने में स्टॉक को भाव 17 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी एक शेयर पर 1 रुपये का डिविडेंड दे रही है। कंपनी के शेयर 18 सिंतंबर को क्रॉस-डिविडेंड स्टॉक के तौर पर ट्रेड करेगा। कंपनी योग्य निवेशकों को एक शेयर पर एक रुपये का डिविडेंड देगी।

दिग्जिट निवेशक ने अडानी की कंपनी पर फिर लगाया दाव, खरीद डाले 4.39 करोड़ शेयर



नई दिल्ली, एजेंसी। गौतम अडानी समूह के प्रमोटर ने शुक्रवार को ऑन सार्मेट्रिक ट्रांजैक्शन के जरिये अंबुजा सीमेंट्स में लगभग 2.8 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच दी है। यह हिस्सेदारी बेचने की ओपन अपर्टमेंट्स को प्राप्त कर रखी है। कंपनी के शेयर 18 सिंतंबर को क्रॉस-डिविडेंड स्टॉक के तौर पर ट्रेड करेगा। कंपनी योग्य निवेशकों को एक शेयर पर एक रुपये का डिविडेंड देगी।

अंबुजा सीमेंट्स में हिस्सेदारी 1.35 प्रतिशत से बढ़कर 3.13 प्रतिशत हो गई है।

डीएचीवी: एमएड पाठ्यक्रम की परीक्षा घोषित, दूसरे सेमेस्टर की 21 सितंबर से

इंदौर। देवी अहिल्या

विश्वविद्यालय ने एमएड पाठ्यक्रम की परीक्षा घोषित कर दी। तीन महीने पिछले परीक्षा सिंतंबर में रखी है, जिसमें दूसरे तीसरे सेमेस्टर के प्रस्तुत एक साथ होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने महीने भर पहले इन पाठ्यक्रम की परीक्षा का शेयर्याल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। एमएड दूसरे सेमेस्टर की 20 से 25 सितंबर और एमएड तीसरे सेमेस्टर की 21 से 26 सितंबर के बीच परीक्षा होगी। दूसरे तीसरे सेमेस्टर में तीन-तीन दोपहर रुक्के हैं। अब

विद्यार्थियों से परीक्षा कर्म भरवाया जा रहा है। दोनों परीक्षा में करेब एक हजार विद्यार्थी समिति होगी। तीन से चार केंद्र पर परीक्षा होगी। अधिकारियों के मुताबिक कालेजों को सितंबर तीसरे सप्ताह तक इंटरनल परीक्षा करवाना है। उसके अंतर्गत विद्यालय को अन्ताइन जमा करवाना होगा।

परीक्षा नियंत्रक डॉ. अशेष तिवारी के मुताबिक परीक्षा होने के बाद विद्यार्थियों की उत्तरपुस्तिका का सूच्यकान शुरू किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक कालेजों को सितंबर तीसरे सप्ताह तक रोकने के लिए केंद्रों द्वारा नकल रोकने के लिए केंद्रों पर उड़नदस्त दल निगरानी रखेगा।

मार्क्स भी विश्वविद्यालय की परीक्षा घोषित कर दी। तीन महीने पिछले परीक्षा सिंतंबर में रखी है, जो 11 सितंबर तक चलेगी। ये सभी परीक्षाएं सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे वाले सत्र में रखी हैं। परीक्षा के दौरान नकल रोकने के लिए केंद्रों पर उड़नदस्त दल निगरानी रखेगा।

बताते हैं कि एमएड दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा 3 सितंबर से रखी है, जो 11 सितंबर तक चलेगी। ये सभी परीक्षाएं सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे वाले सत्र में रखी हैं। परीक्षा के दौरान नकल रोकने के लिए केंद्रों पर उड़नदस्त दल निगरानी रखेगा।

बताते हैं कि एमएड दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा 3 सितंबर से रखी है, जो 11 सितंबर तक चलेगी। ये सभी परीक्षाएं सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे वाले सत्र में रखी हैं। परीक्षा के दौरान नकल रोकने के लिए केंद्रों पर उड़नदस्त दल निगरानी रखेगा।

CBSE, ISTM join forces to launch 2-day 'Training of Trainers' certification course for teachers and heads

(23rd Aug to 24th Aug 2024)

विवाल्य प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्कार



The Central Board of Secondary Education, CBSE, has signed an MoU with the Institute of Secretariat Training and Management (ISTM) under the Department of Personnel & Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, for conducting a 2-day Training of Trainers (ToT) Certification Course. The pilot programme of the curriculum was launched on Friday, August 23, 2024, at the Academic Block of ISTM at Olof Marg in New Delhi by CBSE Chairman Rahul Singh. The training course aligns with the National Education Policy (NEP) 2020 which mandates 50 hours of continuous professional development for all teachers/head teachers. Notably, ISTM is known for its expertise in delivering core training skills which involves Direct Trainers Skills (DTS) and Design of Training (DoT). The ToT has been designed by merging the core components of DTS and DoT and the Integrated Approaches to Child & Adolescent Development.

CBSE Chairman Singh emphasized the

need to empower schools to transition towards new-age learning mechanisms that closely reflect the future of work. "Realizing this vision in a bid to make India a developed nation by 2047 as well as improve the quality of education, CBSE took up this initiative which would go a long way in achieving training standards," he said. CBSE is targeting to train nearly 15,000 Resource Persons (RPs) in several

batches. Additionally, the board will be catering to the training needs of 13 lakh teachers in its affiliated schools through this trained pool of resource persons.

The training course will also help in progressing in accordance with the competency parameters ('Skilled', 'Advanced', and 'Expert') defined in the National Professional Standards for Teachers (NPST). On successful completion

Ministry of Education urges states to enforce school safety guidelines

The Ministry of Education has issued a directive to all States and Union Territories (UTs) to implement the "Guidelines on School Safety and Security-2021" to enhance the protection of children in educational institutions. This move follows directives from the Supreme Court in Writ Petitions (Criminal) No. 136 of 2017 and (Civil) No. 874 of 2017. The guidelines, aligned with the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, are designed to establish clear accountability for school management across Government, Government-aided, and Private Schools. Key aspects include preventive education, reporting procedures, legal provisions, support services, and the creation of a safe environment conducive to learning.

The Ministry has requested States and UTs to provide updates on the notification status of these guidelines within their jurisdictions. The guidelines, which were initially circulated on October 1, 2021, and are advisory in nature, offer flexibility for States to tailor them to local needs. They stress a 'Zero Tolerance Policy' towards negligence regarding child safety. The purpose of these guidelines is to create an understanding among all stakeholders, including students and parents, on the need for co-creating a safe and secure school environment for the holistic development of children and to make different stakeholders aware about the acts, policies, procedures and guidelines already available on different aspects of safety and security i.e., physical, socio-emotional, cognitive and specific to natural disasters as well.

The guidelines are made to empower different stakeholders and enable clarity on their role in the implementation of this guideline. It is to fix accountability for keeping children safe and secure in schools (including while children are transported to and fro, to attend school or go back to their homes in a school transport) on School Management and Principals and Teachers in Private/Uaided Schools, and Head/in-charge Head of School, Teachers and education administration in case of government/government-aided schools.

The guidelines are made to empower different stakeholders and enable clarity on their role in the implementation of this guideline. It is to fix accountability for keeping children safe and secure in schools (including while children are transported to and fro, to attend school or go back to their homes in a school transport) on School Management and Principals and Teachers in Private/Uaided Schools, and Head/in-charge Head of School, Teachers and education administration in case of government/government-aided schools.

Candidates will have to use their registration number, roll number, or name along with their date of birth and other required details to check the status of their application and download the SSC CGL 2024 admit

Australia tightens visa regulations for Int'l students amid surge in enrollment

The Australian government has implemented stricter visa regulations to manage the quality of international students and address visa misuse. According to TravelBiz, international student enrollment in Australia has increased, with more students choosing Australian universities. Research from International Education Data shows that, as of April 2024, there have been 780,104 international student enrollments, a 16 per cent rise from the same period in 2019.

Recent changes to visa rules

TravelBiz reports that the Australian government has revised its student visa regulations to better manage the flow of international students. These changes aim to improve the student experience but also introduce stricter requirements. One major change is the increase in English proficiency standards. Australia has raised the English language requirements for student visa applicants to ensure they can fully engage in their education and daily life. Previously, lower minimum scores were acceptable on tests like IELTS, TOEFL, or PTE. The new requirement demands an increase in proof of funds, including living costs, tuition, and travel expenses.

Australia has also introduced

scores, reflecting a stronger command of English. This change is intended to help students better integrate into the academic environment but may pose challenges for non-native English speakers.

Financial requirements- The Australian government has tightened financial proof requirements to ensure international students have sufficient funds for their stay. Previously, lower proof of financial stability covering living expenses and tuition was required. The new requirement demands an increase in proof of funds, including living costs, tuition, and travel expenses.

Australia has also introduced policies to block non-genuine students from entering the country. These new measures are designed to protect the integrity of the student visa system. In addition, visa application fees have increased. The new fee is AUD 1,600, up from around AUD 630. Reports from Enjoy Your Travel indicate that an Australian visitor visa application cost AUD 140 (about 51,000 Naira) last year. Furthermore, temporary graduate visas are now limited to graduates aged

35 and under. The two-year extension for temporary graduate visas has been removed, and the introduction of the Genuine Temporary Entrant (GTE) criteria requires detailed personal statements and evidence of intent to return home. New regulations also include stricter compliance requirements and regular audits for educational institutions. There is increased support for high-need areas, with new incentives such as scholarships, reduced fees, and expedited visa processing for fields like health and education.

What you should know- To navigate these new regulations, students should apply early to manage document requirements and potential issues. They must also provide evidence of financial stability to cover study and living costs and improve their English proficiency by taking recognized tests. Australia remains a key destination for international students, and understanding these changes can help students achieve their academic goals in Australia's education system.

NEET PG 2024 result out at natboard.edu.in

The result of the National Eligibility cum Entrance Test for Postgraduate (NEET PG) 2024 has been announced. Candidates who have appeared in the test can now check it on the official website of the National Board of Examinations in Medical Sciences, natboard.edu.in. The NBEMS has only shared the marks secured by the candidates in the result document, and detailed scorecards will

be released on August 30, 2024. The board has also shared the cut-off marks for different categories. Those who have secured equal to or more than the mentioned cut-off marks are eligible to apply for counselling. Next, the Medical Counselling Committee (MCC) and the respective state counselling authorities will hold NEET PG counselling for postgraduate medical admissions. The

schedule for the All India Quota (AIQ) NEET PG counselling will be released soon on mcc.nic.in. The entrance test is held every year for admission to MD/MS/DNB/Diploma courses at participating institutions across the country. This year, the test took place on August 11 (Sunday), in two shifts. For further updates, candidates should visit the official website of NBEMS.

GATE 2025: Registration Date Revised

Registrations for the Graduate Aptitude Test in Engineering (GATE) 2025 will commence on August 28 and conclude on September 26, 2024, as per the revised schedule. The exam is set to be held on February 1, 2, 15, and 16, 2025, for admission to postgraduate engineering programmes. GATE 2025 will be conducted in computer-based test (CBT) mode, with city centers divided into eight zones.

Revised Schedule

- Opening Date of GATE Online Application Processing System (GOAPS): August 28, 2024
- Closing Date of regular online registration/application process (without late fee): September 26, 2024
- Closing Date of extended online registration/application process (with late fee): October 7, 2024
- examination dates: February 1, 2, 15, and 16, 2025
- result date: March 19, 2025

The GATE exam is a nationwide test that assesses candidates' knowledge in various undergraduate-level disciplines. Successful qualifiers can pursue Master's and Doctoral programmes, potentially with financial aid. GATE scores are also considered by educational institutions and Public Sector Undertakings (PSUs) for recruitment processes.

Paper Pattern- GATE 2025 will consist of 30 examination papers, allowing candidates to choose one or two test papers from permissible combinations. The exam duration will be three hours, and GATE scores will be valid for three years from the result announcement date. The exam will feature questions in three formats: Multiple Choice Questions (MCQ), Multiple Select Questions (MSQ), and Numerical Answer Type (NAT) questions. Candidates will be evaluated on Recall, Comprehension, Application, Analysis, and Synthesis.

Eligibility Criteria- Candidates are advised to ensure they meet the eligibility criteria for GATE 2025 before submitting an application. Candidates in the third or higher years of any undergraduate degree programme, or those who have completed any government-approved degree programme in Engineering, Technology, Architecture, Science, Commerce, Arts, or Humanities, are eligible to appear in the GATE exam.

शिखर धवन ने क्रिकेट को कहा अलविदा

शिखर धवन

प्रारूप	मैच	रन	शतक	अर्धशतक
टेस्ट	34	2315	7	5
वनडे	167	6793	17	39
टी20	68	1759	0	11
IPL	222	6769	2	51

भावक संदेश में बोले- दिल में भारत के लिए खेलने का सुझून

नई दिल्ली, एजेंसी। धवन ने 10 दिसंबर 2022 को अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला बांगलादेश के खिलाफ खेला था। वनडे प्राप्त का यह मुकाबला चाटांग में खेला गया था। इस मैच धवन महज तीन रन बना पाए थे। इसी तरह धवन ने अपना आखिरी टी20 मैच कोलंबो में 29 जुलाई 2021 को श्रीलंका में खेला था। इस मैच में वे खेला थे और धवन ने अपना आखिरी टेस्ट सिंतंबर 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में खेला था। इस मैच की दोनों पारियों में तीन और एक रन बनाए थे।

शिखर धवन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का एलान कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घेरलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा। एक जब मैं लिए दिल में एक सुझून है कि मैं लंबे समय तक देश के लिए खेला। मैं बीसीसीआई और डीसीसीए को भी शुक्रिया कहना चाहूँगा कि उन्होंने इस मैट्च में सबसे सफल बल्लेबाज़ों में एक है।

वह सर्वाधिक बनने के मामले में विराट कोहली के बाद दूसरे स्थान पर है। धवन ने 222 आईपीएल मैचों में 6769 रन बनाए हैं। इस दौरान दो शतक और 51 अर्धशतक लगाए हैं। धवन का औसत 35.26 और स्ट्राइक रेट 127.14 का रहा है।

शिखर धवन का टेस्ट करियर

धवन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोहली में पहला टेस्ट खेला था। 2013 से वह अब तक 34 टेस्ट में हिस्सा ले चुके हैं। धवन को पिछली बार 2018 में टेस्ट मैच में खेलने का मौका मिला था। उन्होंने क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में 40.61 की औसत से 2315 रन बनाए। इस दौरान सात शतक और पांच अर्धशतक लगाए। धवन का सर्वाधिक स्कोर 190 रन है।

वनडे और टी20 में भी सफल हुए धवन

शिखर ने भारत के लिए पहला वनडे 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्वापृष्ठनम में खेला था। वह 167 मैचों में 6793 रन बना

रोहित शर्मा को IPL 2025 में 50 करोड़ मिलना तय !

● ऑवरशन में आते ही होंगे मालामाल, इन दो टीमों ने कस्ती कमर



नई दिल्ली, एजेंसी। आईपीएल 2025 से पहले मेंगा ऑवरशन होने वाला है। कौन सी टीम किन खिलाड़ियों को रिटेन करेगी, इस तरह के स्वाल ऑवरशन के प्रति लोगों के उत्साह को बढ़ा रहे हैं। आईपीएल में मुंबई इंडियंस की बौत कप्तान 5 वित्ताव जिताने वाले रोहित शर्मा अगले सीजन के लिए इस टीम के साथ बने रहेंगे ये नहीं ये सबसे बड़ा स्वाल है। पिछले सीजन में रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया गया था। ऐसे में माना जा रहा है कि वह अब टीम से अलग हो सकते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। आईपीएल की दो टीमों ने रोहित को अपनी टीम में रखा है।

आईपीएल 2025 से पहले सभी टीमों को कुछ ही खिलाड़ियों को रिटेन करेगी, इस तरह के स्वाल ऑवरशन में नजर आएंगे। इसी बीच कुछ लखनऊ सुपर जायंट्स ने रोहित को खिलाफ लेकर लिया है। यानी ये दोनों टीमों ने रोहित को अपनी टीम में रखा है। इस खबर में कितनी सच्चाई ये बताना मुश्किल है।

रोहित शर्मा ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत डेवेलपर चॉजेंस के लिए खेल रहे हैं। तब से ही वह इसी टीम के लिए खेल रहे हैं। मुंबई की टीम ने आईपीएल 2022 से पहले रोहित को 16 करोड़ रुपए में रिटेन किया था।

रोहित शर्मा को अपने आईपीएल करियर की

शुरुआत डेवेलपर चॉजेंस के साथ की थी। इसके

बाद वह 2011 में मुंबई इंडियंस में शामिल हो गए थे। तब से ही वह इसी टीम के लिए खेल रहे हैं। मुंबई की टीम ने आईपीएल 2022 से पहले रोहित को

शुरुआत के लिए बड़ी रकम खर्च करना चाहती है। हालांकि इस खबर में

कितनी सच्चाई ये बताना मुश्किल है।

रोहित शर्मा ने अपने आईपीएल करियर की

शुरुआत डेवेलपर चॉजेंस के साथ की थी। इसके

बाद वह 2011 में मुंबई इंडियंस में शामिल हो गए थे। तब से ही वह इसी टीम के लिए खेल रहे हैं। मुंबई की टीम ने आईपीएल 2022 से पहले रोहित को

शुरुआत के लिए बड़ी रकम खर्च करना चाहती है। हालांकि इस खबर में

कितनी सच्चाई ये बताना मुश्किल है।

रोहित शर्मा ने अपने आईपीएल करियर की

शुरुआत डेवेलपर चॉजेंस के साथ की थी। इसके

बाद वह 2011 में मुंबई इंडियंस में शामिल हो गए थे। तब से ही वह इसी टीम के लिए खेल रहे हैं। मुंबई की टीम ने आईपीएल 2022 से पहले रोहित को

शुरुआत के लिए बड़ी रकम खर्च करना चाहती है। हालांकि इस खबर में

कितनी सच्चाई ये बताना मुश्किल है।

रोहित शर्मा ने अपने आईपीएल करियर की

शुरुआत डेवेलपर चॉजेंस के साथ की थी। इसके

बाद वह 2011 में मुंबई इंडियंस में शामिल हो गए थे। तब से ही वह इसी टीम के लिए खेल रहे हैं। मुंबई की टीम ने आईपीएल 2022 से पहले रोहित को

शुरुआत के लिए बड़ी रकम खर्च करना चाहती है। हालांकि इस खबर में

कितनी सच्चाई ये बताना मुश्किल है।

रोहित शर्मा ने अपने आईपीएल करियर की

शुरुआत डेवेलपर चॉजेंस के साथ की थी। इसके

बाद वह 2011 में मुंबई इंडियंस में शामिल हो गए थे। तब से ही वह इसी टीम के लिए खेल रहे हैं। मुंबई की टीम ने आईपीएल 2022 से पहले रोहित को

शुरुआत के लिए बड़ी रकम खर्च करना चाहती है। हालांकि इस खबर में

कितनी सच्चाई ये बताना मुश्किल है।

रोहित शर्मा ने अपने आईपीएल करियर की

शुरुआत डेवेलपर चॉजेंस के साथ की थी। इसके

बाद वह 2011 में मुंबई इंडियंस में शामिल हो गए थे। तब से ही वह इसी टीम के लिए खेल रहे हैं। मुंबई की टीम ने आईपीएल 2022 से पहले रोहित को

शुरुआत के लिए बड़ी रकम खर्च करना चाहती है। हालांकि इस खबर में

कितनी सच्चाई ये बताना मुश्किल है।

रोहित शर्मा ने अपने आईपीएल करियर की

शुरुआत डेवेलपर चॉजेंस के साथ की थी। इसके

बाद वह 2011 में मुंबई इंडियंस में शामिल हो गए थे। तब से ही वह इसी टीम के लिए खेल रहे हैं। मुंबई की टीम ने आईपीएल 2022 से पहले रोहित को

शुरुआत के लिए बड़ी रकम खर्च करना चाहती है। हालांकि इस खबर में

कितनी सच्चाई ये बताना मुश्किल है।

रोहित शर्मा ने अपने आईपीएल करियर की

शुरुआत डेवेलपर चॉजेंस के साथ की थी। इसके

बाद वह 2011 में मुंबई इंडियंस में शामिल हो गए थे। तब से ही वह इसी टीम के लिए खेल रहे हैं। मुंबई की टीम ने आईपीएल 2022 से पहले रोहित को

शुरुआत के लिए बड़ी रकम खर्च करना चाहती है। हालांकि इस खबर में

कितनी सच्चाई ये बताना मुश्किल है।

रोहित शर्मा ने अपने आईपीएल करियर की

शुरुआत डेवेलपर चॉजेंस के साथ की थी। इसके

बाद वह 2011 में मुंबई इंडियंस में शामिल हो गए थे। तब से ही वह इसी टीम के लिए खेल रहे हैं। मुंबई की टीम ने आईपीएल 2022 से पहले रोहित को

शुरुआत के लिए बड़ी रकम खर्च करना चाहती है। हालांकि इस खबर में

